AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

डिजिटल शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण भारत का सशक्तिकरण: अवसर, प्रभाव और चुनौतियाँ

ORIGINAL ARTICLE

Author

नेहा मीना
शोधार्थी
राजनीति विज्ञान विभाग
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
वाराणसी, उत्तरप्रदेश, भारत

शोध सार

शिक्षा एक राष्ट्र के विकास का मुख्य आधार है। यह समाज में समानता लाती है, आर्थिक विकास में सहयोग देती है तथा लोगों में तकनीकी समझ विकसित करती हैं। वर्तमान प्रौद्योगिकी युग में विशेषकर कोविड–19 महामारी के साथ शिक्षा के एक नवीन रूप डिजिटल शिक्षा का तेजी से विस्तार हुआ है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करने और शिक्षा के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। यह शोध पत्र ग्रामीण भारत में डिजिटल शिक्षा की भूमिका पर एक अध्ययन है। यह अध्ययन भारत में डिजिटल शिक्षा के विकास का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था पर डिजिटल शिक्षा के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डालता है साथ ही डिजिटल शिक्षा के समक्ष चुनौतियों को भी बताता है। यह अध्ययन वर्णनात्मक शोध पद्धति पर आधारित है, जो प्रासंगिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए द्वितीयक स्रोतों का उपयोग करता है।

मुख्य शब्द

ग्रामीण विकास, डिजिटल शिक्षा, सशक्तिकरण, डिजिटल भारत, शिक्षा में प्रौद्योगिकी.

परिचय

"मैं एक ऐसे डिजिटल भारत का सपना देखता हूं जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, डिजिटल लर्निंग द्वारा संचालित सबसे दुर्गम कोनों तक पहुंचे।"
श्री नरेंद्र मोदी

एक स्वस्थ और विकसित राष्ट्र निर्माण हेतु ग्रामीण विकास मुख्य आधार है। यह ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र उत्थान है। एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक विशिष्ट समूह के लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में सुधार लाने तथा उनकी आजीविका में अभिवृद्धि करती है (विश्व बैंक रिपोर्ट, 1975)। भारत जैसे विकासशील देश की दृष्टि से जहाँ वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत की जनसंख्या 833.1 मिलियन हो, के लिए यह अवश्यंभावी है कि गांव के विकास को महत्ता दी जाए। इसे स्पष्ट करते हुए ''महात्मा गांधी'' ने अपने पत्र ''हरिजन'' में लिखा था कि ''वास्तविक भारत गांवो में निवास करता है। यदि गांव समाप्त होते हैं तो भारत भी समाप्त हो जाएगा'' (सिंह, 2009)।

ध्यातव्य है कि विकास एक बहुआयामी संकल्पना है जिसके अंतर्गत सर्वोन्मुखी विकास को दृष्टिगत रखते हुए

विकास सम्बन्धी नीतियों एवं योजनाओ का निर्माण तथा उनके भली प्रकार क्रियान्वयन को ध्यान में रखकर कार्य किये जाते है। अतः विकास की अवधारणा निम्नांकित सूचकों को इंगित करती हैः

- प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि (आर्थिक विकास),
- आय वितरण में सुधार (समानता),
- राजनीतिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता,
- संसाधनों तक समान पहुंच (शिक्षा, स्वास्थ्य–देखभाल, रोजगार के अवसर और न्याय) (सिंह, 2009)।

इस सर्वोन्मुखी विकास को संभव बनाने में ग्रामीण विकास का अत्यंत महत्व है क्योंकि गांव ही वह मुख्य आधार है जो भारत के भविष्य को स्वर्णिम बना सकता है तथा ग्रामीण विकास व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखते हए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा समृद्ध जीवन के विभिन्न अवयवो की उपलब्धता को सुनिश्चित करने एवं मानव विकास में संसाधनों के पूर्ण उपयोग करने का पक्षधर है तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है जो ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा हमारे दिमाग को खोलती है हमारे क्षितिज का विस्तार करती है और हमारी अज्ञानता को दूर करती है। शैक्षिक प्रणाली हमें आलोचनात्मक और तार्किक सोच हासिल करना और विकसित करना सिखाती है। शिक्षा को मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का सर्वोत्तम गुण (महात्मा गांधी) कहा गया है जिसमे मनुष्य के शरीर एवं आत्मा का पूर्ण विकास करने की क्षमता निहित होती है (प्लेटो) क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को उन्नति के अंतहीन अवसर प्रदान करती है, उसे सभ्य बनाती है, उसमें चुनौतियों से निपटने की क्षमता का विकास करती है एवम् व्यक्ति में उचित और अनुचित की समझ पैदा करती है। इस प्रकार यह मनुष्य के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है (टी.पी. नुन्न)। शिक्षा को सभी समस्याओं, चाहे वे आर्थिक, विकास या जनसंख्या से संबंधित हों, का समाधान भी कहा जा सकता है (अमृत्य सेन)। इस प्रकार शिक्षा मनुष्य को सभ्य, परिष्कृत, सुसंस्कृत एवं शिक्षित बनाने के साथ–साथ समाज की भी समस्याओं यथा गरीबी में कमी, जनसंख्या के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार, आय वितरण में सुधार, परिवार नियोजन पद्धति को अपनाना आदि का समाधान प्रस्तुत करते हुए उसे समृद्धि की ओर अग्रसर करती हैं। एक बेहतर आधुनिक समाज के निर्माण में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है।

अलग–अलग कालखंडो में उक्त भूमिका निभाने के लिए शिक्षा की विभिन्न शिक्षण पद्धतियां रही है। प्राचीन और मध्य काल में जो शिक्षा प्रणाली मौजूद थी वह गुरुकुल एवं औपचारिक प्रकार की थी तथा आधुनिक काल में अंग्रेजो के आगमन के पश्चात्– 1813 के चार्टर एक्ट, मैकाले एक्ट 1835, वुड डिस्पेच 1854 आदि के द्वारा पाश्चात्य शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, महिला शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा को महत्त्व दिया जाने लगा। तत्पश्चात् वर्तमान युग में भूमंडलीकरण के कारण इनफार्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा का स्वरुप अनौपचारिक शिक्षा, डिजिटल शिक्षा, मीडिया शिक्षा, समग्र शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा के रूप में परिवर्तित हो रहा है। हालाँकि नवीन तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के विकास के साथ अन्य शिक्षण पद्धतियों की तुलना में डिजिटल शिक्षा का प्रचलन बढ़ रहा है। डिजिटल शिक्षा, शिक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी, डिजिटल सामग्री और निर्देश का संयोजन है। इसे प्रौद्योगिकी वर्धित शिक्षा (Technology Enhanced Learning), ई–लर्निंग, ऑनलाइन शिक्षा, आभासी (Virtual) शिक्षा आदि के रूप में भी जाना जाता है। यह शोधपत्र भारत में ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने में डिजिटल शिक्षा की भूमिका पर एक अध्ययन है और ग्रामीण समुदाय सशक्तिकरण पर डिजिटल शिक्षा पहलों के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करता है, विशेष रूप से छात्र सशक्तिकरण पर।

साहित्य समीक्षा

डी. एन. सिंह (1985) की सम्पादित पुस्तक 'रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया प्रोब्लम, स्ट्रेटजीज एंड एप्रोचेस' के सम्मिलित लेखों में ग्रामीण विकास को सरल शब्दों में समझाते हुए इसके समक्ष आने वाली बाधाएं एवं उनको दूर करने की विभिन्न रणनीतियाँ व दृष्टिकोणों पर प्रकाश डाला गया है। यह पुस्तक 20वी सदी में ग्रामीण क्षेत्रों की

प्रमुख समस्याओं को उजागर करती है एवं उनके समाधान के लिए सरकार की नीतियां तथा उनके क्रियान्वयन में लोगों की भागीदारी एवं शिक्षा के महत्व को मुख्य सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करती है।

श्रवण कुमार (2020) ने 'राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में ग्रामीण विकास' विषय पर बाड़मेर एवं जालौर जिले के गांवों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया। इस अध्ययन में विकास योजनाओं का मूल्यांकन करते हुए ग्रामीण समाज पर उनके प्रभाव का वर्णन किया। लेखक के अनुसार वित्तीय सहायता, ग्रामीण विकास के लिए विशेष योजनाओं का संचालन, नवीन ऊर्जा के स्रोतों का विकास, ग्राम उद्योग को प्रोत्साहन, मजबूत बैंकिंग प्रणाली, विद्यालय एवं महाविद्यालयों का निर्माण, चिकित्सालय एवं चिकित्सा सुविधाओं के विकास आदि के द्वारा ग्रामीण परिवेश में सुधार करने का प्रयास किया जा सकता है।

नीरज सिंह और एस. मोहित राव (2020) ने 'डिजिटल इंडिया' नए भारत की आकांक्षा लेख में डिजिटल इंडिया को भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के रूप में वर्णित किया है, जिसमें भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में परिणित करने की परिकल्पना निहित है। इस कार्यक्रम के द्वारा सरकार का लक्ष्य देश के हर भाग में उच्च गति इंटरनेट कनेक्टिविटी, वित्तीय समावेशन और कॉमन सर्विस सेंटर तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करना है। इस लेख में लेखक ने इस कार्यक्रम के समक्ष तकनीकी, संगठनात्मक तथा आर्थिक चुनौतियों के अतिरिक्त इनका सफलतापूर्वक सामना करने के उपाय भी बताए हैं। जैसे– नियामक ढांचे में सुधार, परियोजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन, संसाधनों का बेहतर उपयोग, परियोजनाओं में समावेशी भागीदारी को प्रोत्साहन आदि।

अशोक सिंह (2020) ने 'साकार होती डिजिटल भारत की परिकल्पना' लेख में डिजिटल क्रांति की दिशा में भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की सफलता, उपलब्धियां, महत्व आदि के बारे में बताया।

डॉ. कनेश सुरेश (2022) की सम्पादित पुस्तक 'कंटेंपरेरी डेवलपमेंट इश्यू इन साउथ एशिया' के अध्याय–9 'एन ओवरव्यू ऑफ डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया' में बताया गया कि कोरोना महामारी के साथ शिक्षा में डिजिटल मीडिया का प्रयोग पड़ता जा रहा है जिसके परिणामस्वरुप नामांकन, साक्षरता एवं राजस्व में बढ़ोतरी देखने को मिली है। डिजिटल शिक्षा विद्यार्थियों को आसान तरीके से पूर्ण अवधारणा और सिद्धांत सीखने में मदद करती है। इसमें सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध होने से विद्यार्थी देश के किसी भी कोने से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेखक ने डिजिटल शिक्षा को शिक्षा का भविष्य बताया।

रुचिर अरोड़ा (2022) ने 'व्हाय स्टूडेंट्स नीड टू नो अबाउट डिजिटल लिटरेसी' लेख में विद्यार्थियों को डिजिटल टेक्नोलॉजी के सुरक्षित और प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए डिजिटल साक्षरता को अति आवश्यक बताया। ऑनलाइन सामग्री के लिए तार्किक सोच को बढ़ावा देने, सुरक्षित रूप में सोशल मीडिया का उपयोग, साहित्यिक चोरी से बचने, इंटरनेट का सही उपयोग करने, साइबर क्राइम से बचने तथा सर्च इंजन का प्रभावी उपयोग करने के लिए इसे सीखना आवश्यक है।

उद्देश्य

1. भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने में डिजिटल शिक्षा की भूमिका का अध्ययन करना,
2. ग्रामीण परिवेश में छात्र सशक्तिकरण और सामुदायिक विकास पर डिजिटल शिक्षा के प्रभाव का विश्लेषण करना,
3. ग्रामीण भारत में डिजिटल शिक्षा के कार्यान्वयन में प्रमुख बाधाओं की पहचान करना।

शोध पद्धति

इस अध्ययन के लिए शोध पद्धति– डेटा विश्लेषण की वर्णनात्मक पद्धति पर आधारित है, जो प्रासंगिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए द्वितीयक स्रोतों का उपयोग करती है। यह शोध पत्र ग्रामीण भारत मे डिजिटल शिक्षा की भूमिका को समझाने के लिए द्वितीयक डेटा का विश्लेषण और व्याख्या करने पर केंद्रित है। द्वितीयक डेटा में सरकारी

रिकॉर्ड, पुस्तक, पत्रिका, समाचार पत्र, लेख, शोध पत्र, इंटरनेट, वेबसाइट्स, रेपोर्ट्स आदि शामिल है।

भारत में डिजिटल शिक्षा का विकास

भारत में डिजिटल शिक्षा की शुरुआत देखे तो वर्ष 1985 में सर्वप्रथम मुक्त (open) और दूरस्थ (distance) शिक्षा के माध्यम से आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय (वर्तमान में बी.आर. अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय) द्वारा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान पाठ्यक्रम में स्नातक की डिग्री के साथ की गई, इसके पश्चात् इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) द्वारा भी इस डिग्री का प्रारंभ किया गया (सिंह प. औ., 2006)।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 1986 में गैर–औपचारिक (Non-Formal) शिक्षा के द्वारा, आकाशवाणी और दूरदर्शन ने रिकॉर्डेड शिक्षा कार्यक्रम का प्रसारण करके, वर्ष 1994 में इसरो द्वारा नई दिल्ली में इग्नू (IGNOU) मुख्यालय में टेलीकांफ्रेंसिंग सुविधा एवं वर्ष 2000 में ज्ञानदर्शन मंच के तहत टेलीकांफ्रेंसिंग को एक आधिकारिक शिक्षा चौनल के रूप में मान्यता प्रदान करके तथा वर्ष 2005 में इसरो, शिक्षा मंत्रालय और इग्नू के सहयोग से ए. पी.जे. कलाम द्वारा डिजाइन किए गए एडुसैट (EduSat) उपग्रह का प्रक्षेपण करके डिजिटल शिक्षा के प्रसार में योगदान दिया। लेकिन भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बाद और खासकर कोविड–19 के साथ, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में डिजिटल शिक्षा का तेजी से विस्तार हो रहा है। समाज के डिजिटलीकरण की दिशा में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम एक मुख्य कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में 9 स्तंभों की संरचना की गई है। लगातार बदलती तकनीक और नवाचारों को देखते हुए डिजिटल शिक्षा की दिशा में भारत और राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाएं और पोर्टल चलाए जा रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान, स्वयं, स्वयंप्रभा, वर्चुअल लैब, ई–ज्ञानकोश, ज्ञानवाणी, दीक्षा, ई–पाठशाला, शाला दर्पण आदि।

वर्ष 2019–20 की कोरोना महामारी में जब सम्पूर्ण विश्व में लॉकडाउन का माहौल था, डिजिटल या ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से ही शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से किया जा सका। इस समय ही शिक्षा मंत्रालय ने भी विद्यालय रैंकिंग में डिजिटल लर्निंग को एक पैरामीटर के रूप में स्वीकार किया, जिसके आधार पर अब विद्यालयों को रैंक दी जाती है।

डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व को देखते हुए 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' में भी विद्यालय और उच्चतर शिक्षा दोनों में शिक्षण, मूल्यांकन, नियोजन, प्रशासन आदि में सुधार हेतु स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (National Educational Technology Forum) के निर्माण तथा सार्वजनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर; ऑनलाइन शिक्षण मंचन; डिजिटल रिपोजिटरी का विकास; डिजिटल अंतर को कम करने पर बल; वर्चुअल लैब्स; शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण; ऑनलाइन मूल्यांकन एवं परीक्षाएं आदि अनुशंसा की गई है।

ग्रामीण भारत में डिजिटल शिक्षा का प्रभाव

लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण आबादी वाले भारत देश का उन्नत एवं तीव्र विकास ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग से ही संभव है। वर्तमान प्रौद्योगिकी युग में ग्रामीण भारत में विकास के महत्त्वपूर्ण घटक शिक्षा, के नवीन स्वरूप डिजिटल शिक्षा ने देश के विकास में अपनी उपयोगिता को साबित भी किया है। नई तकनीक के साथ डिजिटल शिक्षा का दायरा बढ़ रहा है, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आए हैं। एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (रूरल) 2023 में बताया गया की भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में जो विद्यार्थी पंजीकृत हैं उनमें स्मार्टफोन तक पहुंच 74.8 प्रतिशत है, 2021 की रिपोर्ट में यह 67.6 प्रतिशत तक थी वही 2018 की रिपोर्ट में यह 36.5 प्रतिशत ही देखी गई थी जिसे निम्न तालिका द्वारा भी बता सकते हैः

स्मार्टफोन ओनरशिप (स्कूल एनरोल्ड चिल्ड्रन)

ASER रिपोर्ट (रूरल)	रिपोर्ट 2018	रिपोर्ट 2021	रिपोर्ट 2023
भारत – ग्रामीण	36.5 प्रतिशत	67.6 प्रतिशत	74.8 प्रतिशत

(स्रोतः asercentre.org)

सकारात्मक प्रभाव

- ग्रामीण स्कूलों की एक मुख्य समस्या छात्राओं की ड्रॉपआउट दर अधिक होना है लेकिन डिजिटल शिक्षा की विशेषता है कि डिजिटल टूल्स के द्वारा शिक्षा को घर बैठे भी प्राप्त किया जा सकता है परिणामस्वरूप ड्रॉपआउट दर कम हो रही है।
- डिजिटल शिक्षा के द्वारा शिक्षण का स्वरूप बदल रहा है। अब अधिकांश शिक्षक और छात्र अध्ययन सामग्री के लिए डिजिटल सर्चिंग मेथड्स के विपरीत पारंपरिक सर्चिंग मेथड्स उपयोग कर रहे है क्योंकि डिजिटल मेथड्स से विषय की बेहतर समझ मिलती है।
- डिजिटल शिक्षा में अध्ययन सामग्री की विविधता से समय की बचत होती है।
- डिजिटल टेक्नोलॉजी के सुरक्षित और प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए डिजिटल साक्षरता अति आवश्यक है।
- डिजिटल शिक्षा के लिए इंटरनेट, लेपटॉप/कंप्युटर जैसे डिजिटल उपकरणों की आवश्यकता होती है। इनके उपयोग के साथ शिक्षा को बिना किसी भौतिक और भौगोलिक सीमा के प्राप्त किया जा सकता है।
- डिजिटल शिक्षा का संचालन लागत प्रभावी भी है, क्योंकि इसमें मानव शक्ति, बुनियादी ढाँचा और भौतिक संसाधनों की आवश्यकता पारंपरिक शिक्षा की तुलना में कम रहती है।
- डिजिटल तकनीक कक्षा के माहौल को अधिक जीवंत व संवादात्मक बनाती है।
- शिक्षा में डिजिटल मीडिया के प्रयोग द्वारा स्कूल में नामांकन, साक्षरता, राजस्व में बढ़ोतरी देखने को मिली है।
- डिजिटल शिक्षा विद्यार्थियों को आसान तरीके से पूर्ण अवधारणा (Concept) और सिद्धांत (Theory) सीखने में मदद करती है।
- एक समान शिक्षा उपलब्ध कराने में डिजिटल तकनीक उपयोगी साबित हो सकती है।

नकारात्मक प्रभाव

- डिजिटल या ऑनलाइन शिक्षा से सामाजिक अलगाव उत्पन्न होता है, क्योंकि घर पर ही शिक्षा की सुविधा हो जाने से विद्यार्थियों को स्कूल का सामाजिक परिवेश नहीं मिल पता है।
- विद्यार्थियों में रचनात्मकता की कमी होने लगती है।
- विद्यालय आने की अनिवार्यता नहीं होने से शिक्षक और छात्र के बीच संवाद की कमी हो जाती है।
- शिक्षा के लिए डिजिटल उपकरणों पर निर्भरता बढ़ने लगती है।

डिजिटल शिक्षा के समक्ष चुनौतियाँ

भारत सरकार के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बाद एवं विशेषकर कोविड–19 के साथ भारतीय शिक्षा व्यवस्था में डिजिटल शिक्षा का महत्व बढ़ रहा है लेकिन इसके समक्ष कुछ बुनियादी चुनौतियाँ भी है। नेशनल सैंपल सर्वे आर्गेनाइजेशन 75वीं राउंड रिपोर्ट (जुलाई 2017– जून 2018) में बताया गया कि भारत में जहां शहरी क्षेत्रों में कंप्यूटर की उपलब्धता और इंटरनेट तक पहुंच क्रमशः 23.4 प्रतिशत, 42 प्रतिशत है वही ग्रामीण क्षेत्रों में यह मात्र 4.4 प्रतिशत व 14.9 प्रतिशत ही देखी गई हैं जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः

भारत		
	शहरी	ग्रामीण
कंप्यूटर की उपलब्धता	23.4 प्रतिशत	04.4 प्रतिशत
इंटरनेट तक पहुंच	42.0 प्रतिशत	14.9 प्रतिशत

(स्रोतः Report-585-75th-round-Education-final-1507-0.pdf , mospi.gov.in)

स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2021 में यूनेस्को ने भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में कंप्यूटिंग उपकरणों की उपलब्धता एवं इंटरनेट तक पहुंच के आंकड़े जारी किए जिसमे देखा गया कि भारत में विद्यालयों में कंप्यूटिंग उपकरणों की उपलब्धता 22 प्रतिशत है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यह क्रमशः 43 प्रतिशत, 18 प्रतिशत है एवं भारत में विद्यालयों में इंटरनेट तक पहुंच 19 प्रतिशत है तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यह क्रमशः 42 प्रतिशत व 14 प्रतिशत देखी गई हैं जिसे निम्न तालिका द्वारा दिखाया गया हैः

	भारत	शहरी	ग्रामीण
स्कूल में कंप्यूटिंग उपकरणों की उपलब्धता	22 प्रतिशत	43 प्रतिशत	18 प्रतिशत
स्कूल में इंटरनेट तक पहुंच	19 प्रतिशत	42 प्रतिशत	14 प्रतिशत

(स्रोतः No teacher, no class: state of the education report for India, 2021, UNESCO Digital Library)

- 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 69 प्रतिशत ग्रामीण आबादी ही शिक्षित होती है इसलिए अधिकाँश ग्रामीण लोगों में बेसिक कंप्यूटर ज्ञान की भी कमी है।
- **सीमित संसाधनः** अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या के पास डिजिटल उपकरण जैसे कंप्युटर/लेपटॉप/मोबाईल, स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर आदि तक पहुँच नहीं होती।
- **डिजिटल साक्षरता की कमीः** ग्रामीण लोगों में डिजिटल साक्षरता की कमी होने के कारण डिजिटल डिवाइस के सही उपयोग की समझ नहीं होती।
- डिजिटल डिवाइस के अधिक उपयोग से डिजिटल अपराध जैसे साइबर क्राइम, साहित्यिक चोरी आदि में बढ़ोतरी भी हो सकती है।
- निम्नस्तरीय इंटरनेट कनेक्टिविटी।
- बिजली आपूर्ति में कमी।
- डिजिटल डिवाइस और ऑनलाइन अध्ययन सामग्री के स्त्रोत का पर्याप्त ज्ञान नहीं होना।
- प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी।
- डिजिटल उपकरणों का महंगा होना।
- डिजिटल जागरूकता एवं उचित नीतियों का अभाव।
- शैक्षिक संस्थानों में तकनीकी सहयोग की कमी।

निष्कर्ष

ग्रामीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक कल्याण और सामाजिक स्थिति में समग्र सुधार है। यह भारत जैसे देश के व्यापक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहाँ लगभग 70 प्रतिशत आबादी गाँवों में रहती है। हाल के वर्षों में, विशेष रूप से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT), डिजिटल शिक्षा और व्यापक डिजिटलीकरण की उन्नति के साथ, ग्रामीण विकास में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिले हैं। इन डिजिटल उपकरणों ने सूचना तक बेहतर पहुँच, सीखने के अवसरों में वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर आर्थिक संभावनाओं में योगदान दिया है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी के एकीकरण ने ग्रामीण समुदायों के लिए व्यापक ज्ञान प्रणालियों से जुड़ने, कौशल बढ़ाने और विकास प्रक्रिया में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के नए रास्ते खोले हैं।

2019—20 में कोरोना महामारी ने डिजिटल शिक्षा के महत्व को महत्वपूर्ण रूप से उजागर किया, जब सभी शिक्षण संस्थानों को भौतिक रूप से बंद कर दिया गया था तब डिजिटल शिक्षा की महत्ता में वृद्धि हुई। हालाँकि, इसके लाभों के बावजूद, इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी, अपर्याप्त डिजिटल बुनियादी ढाँचा और ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित डिजिटल साक्षरता जैसी कई बुनियादी चुनौतियाँ इसके प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालती हैं। इन चुनौतियों कारण यह अपने पूर्ण लाभकारी स्वरूप में अभी नहीं आ सकी है।

इन सीमाओं को पहचानते हुए, भारत सरकार ने डिजिटल विभाजन को पाटने और शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से कई पहल शुरू की हैं। निरंतर प्रयासों और लक्षित हस्तक्षेपों के साथ, शिक्षा का डिजिटलीकरण भविष्य उन्मुखी प्रतीत हो रहा है। इसमें समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त बनाने की अपार क्षमता है, जो सतत ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

संदर्भ सूची

1. सिंह, डी. एन. (1985) *रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया–प्रोब्लम, स्ट्रेटजीज एंड एप्रोचेस,* आर एल सिंह फाउंडेशन पब्लिकेशन, वाराणसी।
2. सुरेश, कनेश (2022) *कंटेंपरेरी डेवलपमेंट इश्यू इन साउथ एशिया,* कृष्णा पब्लिकेशन हाउस, गुजरात।
3. कावतरा, पी. एस.; और सिंह, नीरज कुमार (2006) ई–लर्निंग इन एल. आई. एस. एजुकेशन इन इंडिया, एशिया पेसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑन लाइब्रेरी एंड इनफॉरमेशन एजुकेशन एंड प्रैक्टिस, अप्रैल 2006, स्कूल ऑफ कम्यूनिकेशन एण्ड इनफार्मेशन, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, सिंगापुर, पृ. 605–611।
4. लोन, जहूर अहमद (2017) टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इन रूरल इंडिया, *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड कंप्यूटिंग,* वॉल्यूम–7, इशू– 7, जुलाई 2017, पृ. 13953–13955।
5. बारेगामा, शिप्रा; और अरोरा, रीता (2021) एनालिसिस ऑफ डिजिटल टूल्स ऑफ़ लर्निंग, *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लनेरी एजुकेशनल रिसर्च,* वॉल्यूम–10, इशू –4(2), अप्रैल 2021, पृ. 185–189।
6. प्रभाकरण, आर.; और महालक्ष्मी, एम. (2019) परफॉर्मेंस ऑफ डिजिटल मीडिया इन रूरल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, *इंफोकारा रिसर्च,* वॉल्यूम– 8, इशू– 12, पृ. 968–977।
7. अग्रवाल, राजीव कुमार (2021) डिजिटल एजूकेशन इन इंडियारू स्कोप एंड चौलेंजेस, *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एडवांस्ड रिसर्च इन कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस,* वॉल्यूम– 04, अप्रैल–जून 2021, पृ. 99–104।
8. कुमार, श्रवण (2020) राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में ग्रामीण विकास (बाड़मेर एवं जालौर जिलों का अध्ययन), जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राज.)।
9. सिंह, नीरज; और राव, एस. मोहित (2020) डिजिटल इंडियाः नए भारत की आकांक्षा, *कुरुक्षेत्र,* दिसंबर 2020, वॉल्यूम– 67, इशू– 2, पृ. 5–9।
10. सिंह, अशोक (2020) साकार होती डिजिटल भारत की परिकल्पना, *कुरुक्षेत्र,* दिसंबर 2020, वॉल्यूम– 67, इशू– 2, पृ. 16–21।
11. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986।
12. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020।
13. इंडिया रिपोर्ट डिजीटल एजुकेशन, 2021।
14. https://www-dnaindia.com/business/report-17-dreams-prime-minister-narendra-modi-has-for-a-digital-india-2100992, Accessed on 16/04/2025
15. https://timesofindia.indiatimes.com/readersblog/mridul-mazumdar/the-history-and-usefulness-of-online-teaching-in-india-20481, Accessed on 18/04/2025
16. https://www.thehindu.com/education/why-students-need-to-know-about-digital-literacy/article65913126.ece, Accessed on 02/04/2025

——==00==——